

::प्रधानआयुक्त (अपील्स) का कार्यालय, वस्तु एवं सेवा कर और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क::  
O/O THE PRINCIPAL COMMISSIONER (APPEALS), GST & CENTRAL EXCISE



द्वितीय तल, जी एम टी भवन / 2<sup>nd</sup> Floor, GST Bhavan  
रेस कोर्स रिंग रोड / Race Course Ring Road  
राजकोट / Rajkot - 360 001

Tele Fax No. 0281 - 2477952/2441142 Email: cexappealsrajkot@gmail.com

रजिस्टर्ड डाक ए.डी.द्वारा :-

क अपील / फाइल नं./  
Appeal / File No.  
V2/6 & 6A/BVR/2019

मूल आदेश नं /  
O.I.O. No.

01/SUPDT/ALANG-3/BVR-2/2018-19  
02/SUPDT/ALANG-3/BVR-2/2018-19

दिनांक /

Date:  
13/12/2018

ख अपील आदेश नं./ (Order-In-Appeal No.):

**BHV-EXCUS-000-APP-107-TO-108-2019**

आदेश का दिनांक /  
Date of Order: 03.05.2019

जारी करने की तारीख /  
Date of issue:

07.05.2019

श्री कुमार संतोष, प्रधान आयुक्त (अपील्स), राजकोट द्वारा पारित /  
Passed by Shri Kumar Santosh, Principal Commissioner (Appeals), Rajkot

ग अपर आयुक्त/ संयुक्त आयुक्त/ उपायुक्त/ महायुक्त आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/ मेवाकर/ वस्तु एवं सेवा कर,  
राजकोट / जामनगर / गांधीधाम द्वारा उपरलिखित जारी मूल आदेश से मुजित: /  
Arising out of above mentioned OIO issued by Additional/Joint/Deputy/Assistant Commissioner, Central Excise/ST / GST,  
Rajkot/Jamnagar/Gandhidham :

घ अपीलकर्ता & प्रतिवादी का नाम एवं पता / Name & Address of the Appellants & Respondent :-  
M/s G.S. Ship Breaking Corporation, Plot No. 90, Ship Breaking Yard, Alang, Bhavnagar.

इस आदेश (अपील) में व्यक्त किए गए व्यक्ति निम्नलिखित तरीके में उपयुक्त प्राधिकरण / प्राधिकरण के समक्ष अपील दायर कर सकता है। /  
Any person aggrieved by this Order-in-Appeal may file an appeal to the appropriate authority in the following way.

(A) सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं मेवाकर अपील न्यायाधिकरण के प्रति अपील, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35B के अंतर्गत एवं  
विन अधिनियम, 1994 की धारा 86 के अंतर्गत निम्नलिखित जगह की जा सकती है। /  
Appeal to Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal under Section 35B of CEA, 1944 / Under Section 86 of the Finance  
Act, 1994 an appeal lies to:-

(i) वर्गीकरण मुद्दों/कम से कम मूल्य/मूल्य निर्धारण/सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं मेवाकर अपील न्यायाधिकरण की विशेष पीठ, ट्रेन्स-ब्लॉक नं. 2, आर.के. पुरम, नई दिल्ली,  
को जमा करना चाहिए। /  
The special bench of Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal of West Block No. 2, R.K. Puram, New Delhi in all matters  
relating to classification and valuation.

(ii) उपरोक्त परिच्छेद 1(a) में ब्रतांग गण अपीलों के अलावा शेष सभी अपीलों में सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं मेवाकर अपील न्यायाधिकरण  
को पश्चिम क्षेत्रीय पीठिका, द्वितीय तल, बहुमाली भवन असावा अहमदाबाद- 380016 को जमा करना चाहिए। /  
To the West regional bench of Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT) at, 2<sup>nd</sup> Floor, Bhaumali Bhawan,  
Asarwa Ahmedabad-380016 in case of appeals other than as mentioned in para- 1(a) above

(iii) अपील न्यायाधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करने के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (अपील) नियमावली, 2001, के नियम 6 के अंतर्गत निर्धारित किए गये  
प्रपत्र EA-3 को चार प्रतियों में दर्ज किया जाना चाहिए। इनमें से कम से कम एक प्रति के साथ, जहां उत्पाद शुल्क की माँग, ब्याज की माँग और लगाया गया  
जुर्माना, रुपये 5 लाख या उससे कम, 5 लाख रुपये या 50 लाख रुपये तक अथवा 50 लाख रुपये से अधिक है तो क्रमशः 1,000/- रुपये, 5,000/- रुपये  
अथवा 10,000/- रुपये का निर्धारित जमा शुल्क की प्रति संलग्न करें। निर्धारित शुल्क का भुगतान, संबंधित अपील न्यायाधिकरण की शाखा के महायुक्त  
रजिस्टार के नाम से किसी भी मार्बजित क्षेत्र के बैंक द्वारा जारी रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया जाना चाहिए। संबंधित ड्राफ्ट का भुगतान, बैंक की उस  
शाखा में होना चाहिए, जहां संबंधित अपील न्यायाधिकरण की शाखा स्थित है। स्थान आदेश (स्टे ऑर्डर) के लिए आवेदन-पत्र के साथ 500/- रुपये का  
निर्धारित शुल्क जमा करना होगा। /

The appeal to the Appellate Tribunal shall be filed in quadruplicate in form EA-3 / as prescribed under Rule 6 of Central Excise  
(Appeal) Rules, 2001 and shall be accompanied against one which at least should be accompanied by a fee of Rs. 1,000/- Rs.5000/-,  
Rs.10,000/- where amount of duty demand/interest/penalty/refund is upto 5 Lac., 5 Lac to 50 Lac and above 50 Lac respectively in the  
form of crossed bank draft in favour of Asst. Registrar of branch of any nominated public sector bank of the place where the bench of  
any nominated public sector bank of the place where the bench of the Tribunal is situated. Application made for grant of stay shall be  
accompanied by a fee of Rs. 500/-.

(B) अपील न्यायाधिकरण के समक्ष अपील, विन अधिनियम, 1994 की धारा 86(1) के अंतर्गत मेवाकर नियमावली, 1994, के नियम 9(1) के तहत निर्धारित  
प्रपत्र S.T.-5 में चार प्रतियों में की जा सकती है एवं उसके साथ जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गयी हो, उसकी प्रति साथ में संलग्न करें (उनमें से एक प्रति  
प्रमाणित होनी चाहिए) और इनमें से कम से कम एक प्रति के साथ, जहां मेवाकर की माँग, ब्याज की माँग और लगाया गया जुर्माना, रुपये 5 लाख या उससे  
कम, 5 लाख रुपये या 50 लाख रुपये तक अथवा 50 लाख रुपये से अधिक है तो क्रमशः 1,000/- रुपये, 5,000/- रुपये अथवा 10,000/- रुपये का निर्धारित  
जमा शुल्क की प्रति संलग्न करें। निर्धारित शुल्क का भुगतान, संबंधित अपील न्यायाधिकरण की शाखा के महायुक्त रजिस्टार के नाम से किसी भी  
मार्बजित क्षेत्र के बैंक द्वारा जारी रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया जाना चाहिए। संबंधित ड्राफ्ट का भुगतान, बैंक की उस शाखा में होना चाहिए, जहां  
संबंधित अपील न्यायाधिकरण की शाखा स्थित है। स्थान आदेश (स्टे ऑर्डर) के लिए आवेदन-पत्र के साथ 500/- रुपये का निर्धारित शुल्क जमा करना  
होगा। /

The appeal under sub section (1) of Section 86 of the Finance Act, 1994, to the Appellate Tribunal Shall be filed in quadruplicate in  
Form S.T.5 as prescribed under Rule 9(1) of the Service Tax Rules, 1994, and Shall be accompanied by a copy of the order appealed  
against (one of which shall be certified copy) and should be accompanied by a fees of Rs. 1000/- where the amount of service tax &  
interest demanded & penalty levied of Rs. 5 Lakhs or less, Rs.5000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty  
levied is more than five lakhs but not exceeding Rs. Fifty Lakhs, Rs.10,000/- where the amount of service tax & interest demanded &  
penalty levied is more than fifty Lakhs rupees, in the form of crossed bank draft in favour of the Assistant Registrar of the bench of  
nominated Public Sector Bank of the place where the bench of Tribunal is situated. / Application made for grant of stay shall be  
accompanied by a fee of Rs.500/

विन अधिनियम, 1994 की धारा 86 की उप-धाराओं (2) एवं (2A) के अंतर्गत दर्ज की गयी अपील, सेवाकर नियमवली, 1994, के नियम 9(2) एवं 9(2A) के तहत निर्धारित प्रपत्र S.T.-7 में की जा सकती एवं उसके साथ आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अथवा आयुक्त (अपील), केन्द्रीय उत्पाद शुल्क द्वारा भारत आदेश की प्रतियाँ मंलग्र करें (उनमें से एक प्रति प्रमाणित होनी चाहिए) और आयुक्त द्वारा महायुक्त आयुक्त अथवा उत्पाद शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/सेवाकर, को अपीलीय न्यायाधिकरण को आवेदन दर्ज करने का निर्देश देने वाले आदेश की प्रति भी साथ में मंलग्र करनी होगी। / The appeal under sub section (2) and (2A) of the section 86 the Finance Act 1994, shall be filed in Form ST.7 as prescribed under Rule 9 (2) & 9(2A) of the Service Tax Rules, 1994 and shall be accompanied by a copy of order of Commissioner Central Excise or Commissioner, Central Excise (Appeals) (one of which shall be a certified copy) and copy of the order passed by the Commissioner authorizing the Assistant Commissioner or Deputy Commissioner of Central Excise/ Service Tax to file the appeal before the Appellate Tribunal.

- (ii) निम्ना शृल्ल, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय प्राधिकरण (सेन्ट्रल) के प्रति अपीलों के मामले में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 की धारा 35एके अंतर्गत, जो की विनियम अधिनियम, 1994 की धारा 83 के अंतर्गत सेवाकर को भी लागू की गई है, इन आदेश के प्रति अपीलीय प्राधिकरण में अपील करने समय उत्पाद शुल्क/सेवा कर मांग के 10 प्रतिशत (10%), जड़ मांग एवं जमाना विवादित है, या जमाना, जब केवल जमाना विवादित है, का भुगतान किया जाए, वशत कि इन धारा के अंतर्गत जमा कि जात वाली अपेक्षित देय राशि दस करोड़ रुपय से अधिक न हो।
  - (i) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर के अंतर्गत "मांग किए गए शुल्क" से निर्र थापित है
  - (ii) धारा 11 डी के अंतर्गत रकम
  - (iii) सेन्ट्रल जमा की की गई राशत राशि
  - (iii) सेन्ट्रल जमा नियमावली के नियम 6 के अंतर्गत देय रकम

- वशत यह कि इन धारा के प्रावधान विनियम (नं. 2) अधिनियम 2014 के अंश में पूर्व किमी अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष विचारार्थीन स्थगन अर्जी एवं अपील की लागू नहीं होगी। / For an appeal to be filed before the CESTAT, under Section 35F of the Central Excise Act, 1944 which is also made applicable to Service Tax under Section 83 of the Finance Act, 1994, an appeal against this order shall lie before the Tribunal on payment of 10% of the duty demanded where duty or duty and penalty are in dispute, or penalty alone is in dispute, provided the amount of pre-deposit payable would be subject to a ceiling of Rs. 10 Crores,

Under Central Excise and Service Tax, "Duty Demanded" shall include :

- (i) amount determined under Section 11 D;
- (ii) amount of erroneous Cenvat Credit taken;
- (iii) amount payable under Rule 6 of the Cenvat Credit Rules

- provided further that the provisions of this Section shall not apply to the stay application and appeals pending before any appellate authority prior to the commencement of the Finance (No.2) Act, 2014.

(C) भारत सरकार को पुनरीक्षण आवेदन :  
**Revision application to Government of India:**

इन आदेश को पुनरीक्षणार्थीका निम्नलिखित मामलों में, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1994 की धारा 35EE के प्रथमपठक के अंतर्गत अवर नचिव, भारत सरकार, पुनरीक्षण आवेदन इकाई, विन मंत्रालय, राजस्व विभाग, चौथी मंजिल, जीवन दीप भवन, नमद मार्ग, नई दिल्ली-110001, का किया जाता चाहिए। / A revision application lies to the Under Secretary, to the Government of India, Revision Application Unit, Ministry of Finance, Department of Revenue, 4th Floor, Jeevan Deep Building, Parliament Street, New Delhi-110001, under Section 35EE of the CEA 1944 in respect of the following case, governed by first proviso to sub-section (1) of Section-35B ibid:

- (i) यदि माल के किमी तुरन्तान के मामले में, जहाँ तुरन्तान किमी माल को किमी कारखाने से भंडार गृह के पारगमन के दौरान या किमी अन्य कारखाने या फिर किमी एक भंडार गृह से दूसरे भंडार गृह पारगमन के दौरान, या किमी भंडार गृह में या भंडारण में माल के प्रसंस्करण के दौरान, किमी कारखाने या किमी भंडार गृह में माल के तुरन्तान के मामले में। / In case of any loss of goods, where the loss occurs in transit from a factory to a warehouse or to another factory or from one warehouse to another during the course of processing of the goods in a warehouse or in storage whether in a factory or in a warehouse

- (ii) भारत के बाहर किमी गृह या क्षेत्र को निर्यात कर रहे माल के विनिर्माण में प्रयुक्त कच्चे माल पर भरी गई केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के छूट (रिबेट) के मामले में, जो भारत के बाहर किमी गृह या क्षेत्र को निर्यात की गयी है। / In case of rebate of duty of excise on goods exported to any country or territory outside India of on excisable material used in the manufacture of the goods which are exported to any country or territory outside India.

- (iii) यदि उत्पाद शुल्क का भुगतान किए बिना भारत के बाहर, नेपाल या भूटान को माल निर्यात किया गया है। / In case of goods exported outside India export to Nepal or Bhutan, without payment of duty.

- (iv) मुनिश्चित उत्पाद के उत्पादन शुल्क के भुगतान के लिए, जो झुटी क्रेडिट इस अधिनियम एवं इसके विभिन्न प्रावधानों के तहत मान्य की गई है और ऐसे आदेश जो आयुक्त (अपील) के द्वारा विन अधिनियम (नं. 2), 1998 की धारा 109 के द्वारा नियत की गई तारीख अथवा समायाविधि पर या बाद में पारित किए गए हैं। / Credit of any duty allowed to be utilized towards payment of excise duty on final products under the provisions of this Act or the Rules made there under such order is passed by the Commissioner (Appeals) on or after, the date appointed under Sec. 109 of the Finance (No.2) Act, 1998.

- (v) उपरोक्त आवेदन की दो प्रतियाँ प्रपत्र संख्या EA-8 में, जो की केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (अपील) नियमावली, 2001, के नियम 9 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट है, इन आदेश के मंलग्रण के 3 माह के अंतर्गत की जानी चाहिए। उपरोक्त आवेदन के साथ मूल आदेश व अपील आदेश की दो प्रतियाँ मंलग्र की जानी चाहिए। साथ ही केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35-EE के तहत निर्धारित शुल्क की अदायगी के माध्यम के तौर पर TR-6 की प्रति मंलग्र की जानी चाहिए। / The above application shall be made in duplicate in Form No. EA-8 as specified under Rule, 9 of Central Excise (Appeals) Rules, 2001 within 3 months from the date on which the order sought to be appealed against is communicated and shall be accompanied by two copies each of the OIO and Order-In-Appeal. It should also be accompanied by a copy of TR-6 Challan evidencing payment of prescribed fee as prescribed under Section 35-EE of CEA, 1944, under Major Head of Account.

- (vi) पुनरीक्षण आवेदन के साथ निम्नलिखित निर्धारित शुल्क की अदायगी की जानी चाहिए। जाए और यदि मंलग्र रकम एक लाख रुपये से ज्यादा हो तो रुपये जहाँ मंलग्र रकम एक लाख रुपये या उससे कम हो तो रुपये 200/- का भुगतान किया जाए और यदि मंलग्र रकम एक लाख रुपये से ज्यादा हो तो रुपये 1000-/- का भुगतान किया जाए। / The revision application shall be accompanied by a fee of Rs. 200/- where the amount involved in Rupees One Lac or less and Rs. 1000/- where the amount involved is more than Rupees One Lac.

- (D) यदि इन आदेश में कई मूल आदेशों का समावेश है तो प्रत्येक मूल आदेश के लिए शुल्क का भुगतान, उपर्युक्त ढंग से किया जाना चाहिए। इस तथ्य के होने हुए भी की लिखा पढी कार्य से बचन के लिए यथान्धिति अपीलीय न्यायाधिकरण को एक अपील या केन्द्रीय सरकार को एक आवेदन किया जाना है। / In case, if the order covers various numbers of order- in Original, fee for each O.I.O. should be paid in the aforesaid manner, notwithstanding the fact that the one appeal to the Appellant Tribunal or the one application to the Central Govt. As the case may be, is filled to avoid scriptoria work if excising Rs. 1 lakh fee of Rs. 100/- for each.

- (E) दशमंशोधित न्यायालय शुल्क अधिनियम, 1975, के अनुसूची-1 के अनुसार मूल आदेश एवं स्थगन आदेश की प्रति पर निर्धारित 6.50 रुपये का न्यायालय शुल्क टिकट लगा होना चाहिए। / One copy of application or O.I.O. as the case may be, and the order of the adjudicating authority shall bear a court fee stamp of Rs.6.50 as prescribed under Schedule-I in terms of the Court Fee Act, 1975, as amended.

- (F) निम्ना शृल्ल, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (कार्य विधि) नियमावली, 1982 में वर्णित एवं अन्य संबन्धित मामलों को सम्मिलित करने वाले नियमों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है। / Attention is also invited to the rules covering these and other related matters contained in the Customs, Excise and Service Appellate Tribunal (Procedure) Rules, 1982.

- (G) उच्च अपीलीय प्राधिकारी को अपील दाखिल करने में संबंधित व्यापक, विस्तृत और नवीनतम प्रावधानों के लिए, अपीलाधी विभागीय वेबसाइट [www.cbec.gov.in](http://www.cbec.gov.in) को देख सकते हैं। / For the elaborate, detailed and latest provisions relating to filing of appeal to the higher appellate authority, the appellant may refer to the Departmental website [www.cbec.gov.in](http://www.cbec.gov.in).

**:: ORDER-IN-APPEAL ::**

M/s. G.S. Ship Breaking Corporation, Plot No. 90, Ship Breaking Yard, Alang, Bhavnagar (*hereinafter referred to as 'Appellant'*) filed the present appeal against Orders-in-Original No. 01 & 02/SUPDT/ALANG-3/BVR-2/2018-19 dated 13.12.2018 (*hereinafter referred as "the impugned orders"*) passed by Superintendent, Central GST & Central Excise, Alang-3, SBY, Alang (*hereinafter referred to as "the lower adjudicating authority"*).

2. The brief facts of the case are that Appellant was issued Show Cause Notices No. CGST/AR-II/Alang/SCN/G.S.-90/2016-17 dated 19.12.2016 & dated 13.7.2018 on the ground that they did not file E.R.-1 monthly return in time but late in contravention of Rule 12(1) of the Central Excise Rules, 2002 (*hereinafter referred to as "the CER"*) during the period from April-2015 to November-2016 and December-2016 to February-2017 respectively, and therefore, penalty under Rule 12(6) of the CER was proposed to be imposed on them. The Show Cause Notices were adjudicated by the lower adjudicating authority vide the impugned orders by imposing penalty of Rs. 3,35,000/- and Rs. 6,900/- respectively under Rule 12(6) of the CER.

3. Being aggrieved with the impugned orders, Appellant preferred these appeals, inter-alia, on the grounds that the Appellant had neither imported any ship nor carried out any manufacturing activity during the period under consideration and therefore, no penalty is imposable on them; that the appellant relied upon a decision of the Hon'ble CESTAT in the case of Ashok Rastogi reported as 1998 (104) ELT 480 (Tri); claimed that no penalty is imposable on them as no business was carried out by them during the period under question; that quantum of penalty cannot be more than the duty involved as laid down in the case of M/s. Sonex Chemicals reported as 2003(156) ELT 1024(Trib) and since all returns are nil, no penalty is imposable on them under Rule 12(6) of the CER.

3.1 Vide letter dated 12.4.2019, Appellant further submitted a copy of Panchnama dated 24.7.2008 drawn by the Port Officer, Ship Recycling Yard, Alang to the effect that Plot No. 90 belonging to M/s. G.S. Shipbreaking was taken over by them as M/s. G. S. Shipbreaking could not pay outstanding renewal charges for Plot No. 90 of the Yard to Gujarat Maritime Board.



4. Personal hearing in the matter was attended by Shri Ghanshayam Harsora, Accountant, who reiterated the grounds of appeals and submitted that they did not get any order to undertake any ship breaking till date; that only mistake they committed that they did not file returns in time; that it happened because the owner/Appellant is illiterate person and the then Accountant, had been removed and Appellant did not file returns under impression that return was not required to be filed since no business was undertaken; that appeals may be allowed by setting aside penalty.

4.1 Personal hearing notices were sent to the Department, however, no officer appeared.

#### FINDINGS :-

5. I have carefully gone through the facts of the cases, the impugned orders and the grounds of appeals and written as well oral submissions made by the appellant. The issue to be decided in the present appeals is as to whether imposition of penalty under Rule 12(6) of the CER is proper and legal or not in the facts and circumstances of the case.

6. The appellant has contended that they have neither carried out any manufacturing activity nor transacted any business during the period under consideration and therefore, no penalty is imposable for late filing of NIL E.R.-1 returns.

7. In this regard, I would like to reproduce the relevant provisions of Rule 12 of the CER read as under :-

*"12(1) (1) Every assessee shall submit to the Superintendent of Central Excise a monthly return in the form specified by notification by the Board, of production and removal of goods and other relevant particulars, within ten days after the close of the month to which the return relates :"*

*"12 (6) Where any return referred to in this rule is submitted after due date as specified for every, return or statement, an amount calculated at the reate of one Hundred Rupees per day subject to a maximum twenty thousand Rupees for the period of delay in submission of each such return of statement shall be payable to the credit of the Central Government."*



*"Provided that in respect of the cases where the details relating to such transactions are recorded in the specified record for the period beginning with the 8th April, 2011 upto the date on which the Finance Bill, 2015 receives the assent of the President (both Days inclusive), the penalty shall be fifty per cent of the service tax so determined."*

7.1 I find that the impugned orders imposed penalty stating as under :-

In view of the above, it is clear that after introduction of Rule 12(6) of the CER, 2002, there is no option with the Noticee but to pay late fee on late filing of Central Excise E.R.1 returns which were filed late (or after due date). Hence the Noticee has to pay the late on late filing of their monthly E.R.1 returns as mentioned below (only returns for the Month April-2015 and May-2015 were filed in time) :

SL. NO.	MONTH	DUE DATE	DATE OF FILING	DAYS DELAY	PENALTY
1	APRIL, 2015	10-May-2015	6-May-2015	0	0
2	MAY, 2015	10-Jun-2015	3-Jun-2015	0	0
1	JUNE, 2015	10-Jul-2015	12-Mar-2017	611	20000
2	JULY, 2015	10-Aug-2015	12-Mar-2017	580	20000
3	AUGUST, 2015	10-Sep-2015	12-Mar-2017	549	20000
4	SEPTEMBER, 2015	10-Oct-2015	12-Mar-2017	519	20000
5	OCTOBER, 2015	10-Nov-2015	12-Mar-2017	488	20000
6	NOVEMBER, 2015	10-Dec-2015	12-Mar-2017	458	20000
7	DECEMBER, 2015	10-Jan-2016	12-Mar-2017	427	20000
8	JANUARY, 2016	10-Feb-2016	12-Mar-2017	396	20000
9	FEBRUARY, 2016	10-Mar-2016	12-Mar-2017	367	20000
10	MARCH, 2016	10-Apr-2016	12-Mar-2017	336	20000
11	APRIL, 2016	10-May-2016	12-Mar-2017	306	20000
12	MAY, 2016	10-Jun-2016	15-Mar-2017	278	20000
13	JUNE, 2016	10-Jul-2016	12-Mar-2017	245	20000
14	JULY, 2016	10-Aug-2016	12-Mar-2017	214	20000
15	AUGUST, 2016	10-Sep-2016	12-Mar-2017	183	18300
16	SEPTEMBER, 2016	10-Oct-2016	12-Mar-2017	153	15300
17	OCTOBER, 2016	10-Nov-2016	12-Mar-2017	122	12200
18	NOVEMBER, 2016	10-Dec-2016	12-Mar-2017	92	9200
19	DECEMBER, 2016	10-Jan-2017	12-Mar-2017	61	6100
20	JANUARY, 2017	10-Feb-2017	12-Mar-2017	30	300
21	FEBRUARY, 2017	10-Mar-2017	15-Mar-2017	5	500
			TOTAL LATE FEE U/RULE 12(6)		3,41,900

7.2 It is a fact that the Appellant failed to file ER-1 Returns for 21 months, which were all NIL returns. However, it is also a fact that the possession of Plot No. 90 where manufacturing activity could have been carried out, was taken over by Gujarat Maritime Board on 24.7.2008 and the appellant could not / did not undertake any work as is evident from letter No. NIL dated 12.4.2019 which is reproduced as under :-

*[Handwritten signature]*

*"Further enclosed is the copy of panchnama dated 24.07.2008 drawn by Port Officer, Ship Recycling Yard, Alang under which our plot was kept possession of by Gujarat Maritime Board....."*

[Emphasis supplied]

7.2.1 Further, letter F. No. GMB/Alang/90/7149 dated 24.9.2003 of Gujarat Maritime Board in connection with Plot No. 90 of SBY, Alang is reproduced as under :-

*"In this connection, in response to this officer letter GMB/Alang/90/7029 dated 20/9/03 a sum of Rs. 1,82,250/- by D.D. No.640337 to 640340 has been paid to this office for change in the name, status and constitution in your firm. This change will affect the status, control and management of the permission holder of Plot No. 90, admeasuring 30mX45m=1350 sq.mts. The said permission was granted for ten years from 8.9.95 to 31.8.2005 vide this office letter No. GMB/T/Alang/Cat-4(A)/119/11191 dtd. 24.01.1995 to M/s. Chaudhary Ship Breakers. Now, M/s. G.S. Ship Breaking Corporation shall utilize the said plot for the remaining period i.e. upto 31.8.2005 only."*

[Emphasis supplied]

7.2.2 In view of the above peculiar facts, I am inclined to take a lenient view relying upon the decision of the Hon'ble CESTAT in the case of Ashok Rastogi reported as 1998 (104) ELT 480 (Tri) wherein it has been held as under :-

*"5. We have carefully considered the submissions. We find that appellant has not carried out any business during the period in question and even if he has filed return in time, the same would have been shown as NIL return. In the similar facts and circumstances of the case, the Tribunal has already waived the amount and allowed the appeal. Following the ratio of that decision, we accept the contentions of the appellant and, accordingly, the appeal is allowed. Both the stay application and appeal are disposed of accordingly."*

7.3 The department has not produced any evidence that the appellant had/has undertaken manufacturing activities there and/or the plot was in possession of the appellant. Since, the plot was in possession of the Gujarat Maritime Board, I hold that the appellant could not have undertaken any activity there.

8. In view of above, I set aside the impugned orders and allow the appeals.

9. अपीलकर्ता द्वारा दर्ज की गई अपील का निपटारा उपरोक्त तरीके से किया जाता है ।

9. The Appeals filed by the appellant stand disposed off in above terms.



*(कुमार संतोष)*

प्रधान आयुक्त (अपील्स)

By R.P.A.D.

To,  
M/s. G.S. Ship Breaking Corporation,  
Plot No. 90,  
Ship Breaking Yard,  
Alang, Bhavnagar.

प्रति :-

- 1) प्रधान मुख्य आयुक्त वस्तु एवं सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, गुजरात क्षेत्र, अहमदाबाद को जानकारी हेतु।
- 2) आयुक्त, वस्तु एवं सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, भावनगर आयुक्तालय, भावनगर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 3) अधीक्षक, वस्तु एवं सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मण्डल - अलंग-3 SBY-अलंग, भावनगर आयुक्तालय, भावनगर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 4) गार्ड फाइल ।

